राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल न्यायमूर्ति आपराधिक जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 159/2022 राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक राजस्थान के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्याम सुंदर मुंडारा पुत्र चंपालाल मुंडारा, निवासी कृष्णा विहार, बी.के. कौल नगर, अजमेर

----प्रत्यर्थी

एस.बी. आपराधिक जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 165/2022 राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्याम सुंदर मुंडारा पुत्र चंपालाल मुंडारा, निवासी कृष्णा विहार, बी.के. कौल नगर, अजमेर।

----प्रत्यर्थी

एकल न्यायमूर्ति आपराधिक जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 166/2022 राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

श्याम सुंदर मुंडारा पुत्र चंपालाल मुंडारा, निवासी कृष्णा विहार, बी.के. कौल नगर, अजमेर।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री जी.एस.राठौड़, जीए सह एएजी श्री संतोष सिंह राठौड़ के साथ श्री लोकेन्द्र, अति. एस. पी
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एस.एस. होरा जी, श्री नीरज पाल सिंह यादव के साथ

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टबल

आदेश सुरक्षित करने की तिथि : 29/05/2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि : 02/06/2023

1. दोनों पक्षों की सम्यक सहमति से, समान तथ्यात्मक मैट्रिक्स से उत्पन्न होने वाले जमानत रद्दीकरण आवेदनों के तत्काल बैच को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।

2. तत्काल जमानत रद्द करने का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत श्याम सुंदर मुंडारा बनाम राजस्थान राज्य शीर्षक वाली आपराधिक विविध मामला संख्या 716/2021 में दिनांक 26.08.2021 के आदेश द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर की जाती है। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन के माध्यम से, मामला सं. 778/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत दिनांक 26.08.2021 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर जमानत रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

आवेदक-राज्य की प्रस्तुतियाँ

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री घनश्याम एस. राठौड़ ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 के आक्षेपित आदेश, तात्विक विचारणों और कानून की स्थापित स्थिति की घोर अज्ञानता में पारित किए गए हैं, और इसलिए, पूरी तरह से विकृत होने के कारण, रद्द और आपास्त किए जाने योग्य हैं। यह कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8/22 और 8/29 के तहत दर्ज अपराध में आरोपी-प्रत्यर्थी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। विद्वान एएजी ने विशेष रूप से निम्नलिखित आधारों पर आरोपी-प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को रद्द करने की प्रार्थना की है:

(क) आरोपी-प्रत्यर्थी के आन्वयिक कब्जे से काफी बड़ी/व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ/मादक दवाएं और मनोदैहिक प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें शामिल हैं;

(i) कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसके लिए एनडीपीएस

अधिनियम के तहत अनुसूची की प्रविष्टि 238 जेडएच के तहत निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है।

(ii) अल्प्राजोलम, जिसके लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत अनुसूची की प्रविष्टि 178 के तहत निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा 100 ग्राम है।]

(ख) कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 26.08.2021 और 27.09.202 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अंतर्विष्ट अवरोधनों का उचित प्रकार से निपटान नहीं किया, जिसके अनुसार, जमानत देने से पहले उक्त अधिनियम के तहत आरोपी के संबंध में *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि आरोपी अपराध कारित करने में शामिल नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया है। ऐसा न करके विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विधिक त्रुट के साथ-साथ तथ्यात्मक त्रुटि भी की है।

(ग) कि 26.08.2021 और 27.09.2021 के आक्षेपित आदेश अपरिपक्व अवस्था में पारित किए गए थे, जबकि मामले में पर्याप्त जांच अभी भी लंबित थी। इस संबंध में, यह दर्शाया गया कि मामले में आरोप पत्र नवंबर, 2021 में दायर किया गया था, जबकि जमानत आदेश काफी पहले पारित किया गया था।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बरामद की गई दवाएं न केवल निर्धारित व्यावसायिक मात्रा की तुलना में काफी अधिक मात्रा में थीं, बल्कि उनका कुल वजन लगभग 3645 किलोग्राम था। (सभी एफआईआर में की गई वसूली को शामिल करते हुए) और उनका संबंधित बाजार मूल्य करोड़ों रुपये था।

(ड.) विद्वान विशेष न्यायाधीश साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए 'प्रकटीकरण बयानों' को समझ पाने में विफल रहे, जिनमें शेख साजिद और कमल दीप मोर्या द्वारा दिए गए बयान भी शामिल हैं, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन के साथ-साथ अवैध/गुप्त खरीद के लिए आरोपी-प्रत्यर्थी की विशिष्ट भूमिकाएं बताई गई हैं।

(च) विद्वान विशेष न्यायाधीश वेलकम फार्मा के आरोपी-प्रत्यर्थी यानी श्याम सुंदर मुंद्रा से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से बरामद 'किराया समझौता' की सराहना करने में विफल रहे, जिस पर हस्ताक्षर थे अभियुक्त-प्रत्यर्थी को गवाह के रूप में दर्शाया गया है।

(छ) एफआईआर को देखने से पता चलता है कि इस मामले में प्रतिबंधित पदार्थों की

आकस्मिक/औचक बरामदगी शामिल है, इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह भी तर्क दिया गया कि संबंधित जांच अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन न करने के कारणों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था।

(ज) एफआईआर, आरोप-पत्र, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयानों के साथ-साथ सीआर.पी.सी. की धारा 164 के तहत सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों का अवलोकन मात्र करने पर, जो आरोपी-प्रत्यर्थी के कर्मचारियों की हैसियत में होने के साथ-साथ प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहनकर्ता के रूप में कथित तौर पर प्रश्नगत अपराध कारित किए जाने में शामिल थे, उपरोक्त व्यक्तियों के बीच *प्रथम दृष्टया* सांठगांठ स्थापित होती है, जो प्रतिबंधित पदार्थों/मादक दवाओं और मनोदैहिक प्रतिबंधित पदार्थों का एक सर्किट चलाते थे, जिसमें मास्टरमाइंड और मुख्य व्यक्ति प्रत्यर्थी-आरोपी था।

4. श्री घनश्याम एस. राठौड़, एएजी ने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 26.08.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा आरोपी-प्रत्यर्थी को जमानत देने के आधार पर, मामले में निष्पक्ष और भार ठोस जांच विकृत हो गई है और/या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई है। उक्त तर्क के समर्थन में, यह कहा गया कि उक्त जमानत दिए जाने के बाद, वर्तमान मामले में जांच अधिकारी, अपनी ओर से कुछ दुर्भावनाओं के कारण, निष्पक्ष तरीके से जांच करने में विफल रहे, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.04.2022 के आदेश के तहत मामले में नियुक्त पहले जांच अधिकारी को अजमेर रेंज से जोधपुर रेंज में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, उनके स्थान पर नियुक्त की गई अगली अधिकारी, सुश्री दिव्या मित्तल, अपर एसपी एसओजी, अजमेर को एफआईआर संख्या 183/2021 के अनुसरण में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत इस आधार पर आरोपी बनाया गया कि सह-आरोपी सुनील नंदवानी, मालिक-हिमालयन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की गिरफ्तारी की मंजूरी दिए जाने के बावजूद, उपर्युक्त अधिकारी सुश्री दिव्या मित्तल ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की और साथ ही इसके लिए कोई उचित आधार भी प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि सुश्री दिव्या मित्तल वर्तमान में विभाग से निलंबित हैं। इस प्रकार यहां ऊपर दी गई दलीलों पर भरोसा करते हुए, जो एक उचित हलफनामे के माध्यम से समर्थित हैं, विद्वान एएजी ने यह तर्क दिया कि यदि आरोपी-प्रत्यर्थी को दी गई जमानत को बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता

है, तो एक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष जांच में हस्तक्षेप के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 के लागू आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और मामले में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी-प्रत्यर्थी को दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए।

5. निर्णायक रूप से, विद्वान एएजी ने **केरल राज्य एवं अन्य बनाम राजेश एवं अन्य: (2020) 12 एससीसी 122, एनसीबी बनाम मोहित अग्रवाल: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1891** और **भारत संघ बनाम अजय कुमार @ पप्पू** शीर्षक के तहत **एसएलपी (अप.) संख्या 2351/2023** में उच्चतम न्यायालय के आदेश और साथ ही **कालूराम बनाम राजस्थान राज्य** शीर्षक के तहत **एकलपीठ अप. विविध जमानत आवेदन संख्या 20010/2021** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।

<u>अभियुक्त-प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ</u>

6. *इसके विपरीत,* आरोपी-प्रत्यर्थी, श्री एस.एस. होरा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन दाखिल करने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 26.08.2021 को प्रत्यर्थी-अभियुक्त की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इसके बाद, राज्य द्वारा दायर जमानत रद्दकरण आवेदन को विशेष न्यायाधीश ने 27.09.2021 को खारिज कर दिया। इसके बाद, राज्य द्वारा वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन 26.08.2022 और 27.08.2022 को, आक्षेपित आदेशों के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद दायर किए गए थे। विलंब के संबंध में उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **कादरा पेहदिया एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** के मामले में दिए गए आदेश **(1981) 3 एससीसी 671** तथा **भारत संघ बनाम जितेंद्र** के मामले में दिए गए आदेश (2021) 10 एससीसी 789 पर भरोसा किया। निर्णायक रूप से यह तर्क दिया गया कि एक बार जब प्रत्यर्थी को जमानत मिल गई है और उसके बाद, वह दिनांक 26.08.2021 के आदेश के तहत अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का विधिवत पालन कर रहा है, तो उक्त जमानत आदेश को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त पर भरोसा करते हुए, साथ ही जमानत रद्दीकरण आवेदन दाखिल करने में हुई भारी देरी के आधार पर, आरोपी-प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदनों को खारिज करने की प्रार्थना की है।

7. यहां ऊपर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के अलावा, आरोपी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने योग्यता के आधार पर वर्तमान आवेदनों को खारिज करने के लिए भी तर्क दिया। श्री एस.एस. होरा ने यह कहा कि:

(क) आरोपी-प्रत्यर्थी के खिलाफ कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें उसे सभी मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि आरोपी-प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर समान लेनदेन से संबंधित थीं और सह-अभियुक्तों और कई आम गवाहों के एक सामान्य सेट के अलावा, इसमें एक समान वर्णन किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त के बावजूद, आवेदक-राज्य ने केवल अजमेर में आरोपी-प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उसे दिनांक 26.08.2021 के आदेश के तहत जमानत दी गई थी, न कि जयपुर में दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी-प्रत्यर्थी को आवेदन संख्या 5657/2022 में दी गई जमानत के आधार पर। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया गया कि आवेदक-राज्य ने एक सामान्य लेनदेन से उत्पन्न होने वाले सभी कथित अपराधों के बावजूद, रद्दकरण आवेदनों को प्राथमिकता देने के लिए मनमाने ढंग से चयन-तंत्र को अपनाया है। अत:, केवल इस आधार पर, वर्तमान रद्दकरण आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।

(ख) कि जिस परिसर से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी, उसकी तलाशी और जब्ती के समय जांच अधिकारियों की ओर से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन नहीं किया गया था।

(ग) आरोपी-प्रत्यर्थी से प्रतिबंधित पदार्थों/प्रतिबंध की कोई सीधी वसूली नहीं की गई थी।

(घ) जांच अधिकारी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, वे स्वीकार्य साक्ष्य नहीं हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों द्वारा वर्जित हैं। इस संबंध में, **तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1** में प्रकाशित किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

(ड.) विद्वान विशेष न्यायाधीश ने, आरोपी-प्रत्यर्थी को जमानत देते समय, अपराध कारित किए जाने में आरोपी-प्रत्यर्थी की गैर-संलिप्तता के संबंध में *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि हासिल की,

जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में दिए गए मापदंडों का विधिवत अनुपालन हुआ। इस संबंध में, **मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली),** (2023) **एससीसी ऑनलाइन एससी 352** में प्रकाशित मामले में उच्चतम अदालत के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

8. इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने निर्णायक रूप से तर्क दिया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है, जिसके तहत उन्होंने सभी भौतिक शर्तों पर विचार किया है, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन धारा 439 सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के आलोक में खारिज किए जाने योग्य हैं। अंत में, अपने तर्कों के समर्थन में, आरोपी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **रणजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 एससीसी 294** और **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929** में प्रकाशित में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा जताया, जो समान विषय-वस्तु से संबंधित हैं जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के समान प्रावधान शामिल थे।

<u>चर्चाएँ और निष्कर्ष</u>

9. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को सुना गया, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और विद्वत-परिषद में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

10. वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन में उठाए गए आधारों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने से पहले, यह न्यायालय जमानत रद्द करने के विषय पर कानून की स्थापित स्थिति को दोहराना उचित समझता है।

11. **नीरू यादव बनाम यूपी राज्य**, **(2014) 16 एससीसी 508** में प्रकाशित, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि:

> *"हमने जमानत देते समय ध्यान में रखे जाने वाले कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जैसा कि समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करना क्योंकि आरोपी स्वयं ही कोई दुर्व्यवहार किया है या कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों के कारण उसे रद्द किया गया है, यह जमानत देने के आदेश से बिल्कुल अलग है, जो कि अनुचित, अवैध या*

विकृत है। यदि किसी मामले में, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से वरिष्ठ अदालत जमानत प्रदान करने के ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है, ऐसा मामला अलग श्रेणी का है और अलग दायरे में है। दूसरी प्रकृति के मामले से निपटते समय, अदालत आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन या उसके बाद होने वाली निगरानी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की औचित्यता और सुदृढ़ता पर प्रकाश डालता है।"

12. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एआईआर 2022 एससी 1910** में प्रकाशित किए गए **वाई बनाम राजस्थान राज्य** में जमानत रद्द करने के विषय का निपटान करते हुए कहा कि:

"यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह इस बात से संबंधित है कि क्या उच्च न्यायालय ने उचित रूप से जमानत देने में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया है। ऐसा मूल्यांकन यह तय करने से अलग है कि क्या जमानत दिए जाने के बाद की परिस्थितियों ने उसे रद्द करना आवश्यक बना दिया है। पहली स्थिति में न्यायालय को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश अवैध, विकृत, अनुचित या मनमाना था। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन में यह देखा जाता है कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं जिनके रद्द करने की आवश्यकता है।"

13. जैसा कि ऊपर बताया गया है, विषय-वस्तु पर कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का संक्षेप में विश्लेषण करना भी उचित समझता है, जो उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत अपराधों के लिए जमानत के विषय पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। त्वरित संदर्भ के लिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे:

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) किसी दंडनीय अपराध के लिए आरोपी किसी भी व्यक्ति को [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-क के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी] जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने

का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या ज़मानत देने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

14. यह विश्लेषण किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम का मानना है कि कोई अदालत किसी आरोपी को जमानत तभी दे सकती है जब वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। तथापि, न्यायालय द्वारा अपेक्षित संतुष्टि केवल *प्रथम दृष्टया* उसके समक्ष साक्ष्य/रिकॉर्ड के उचित अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। इस संबंध में **मोहम्मद मुस्लिम@हुसैन (सुप्रा.)** मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय पर भी भरोसा किया जा सकता है।

15. तदनुसार, यह सुस्थापित है कि तत्काल जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय, इस न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या जमानत देने वाला आक्षेपित आदेश अवैध, विकृत, अनुचित या मनमाना था और/या क्या ऐसी कोई पर्यवेक्षणीय परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण अभियुक्त-प्रत्यर्थी को ऐसी जमानत दी गई को जमानत को रद्द करना पड़ा है।

16. इसलिए, दिनांक 26.08.2021 के आक्षेपित आदेश की औचित्यता और सुदृढ़ता पर निर्णय करने के लिए, हमें उन आधारों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर निचली अदालत ने आरोपी-प्रत्यर्थी द्वारा दायर जमानत आवेदन को अनुमति दी थी। यह देखा गया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत निम्नलिखित आधार पर जमानत आवेदन की अनुमति दी थी:

(क) कि आरोपी-प्रत्यर्थी को केवल सह-आरोपी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर मामले में आरोपी बनाया गया था।

(ख) आरोपी-प्रत्यर्थी से कोई वसूली नहीं की गई थी।

(ग) कि तलाशी और जब्ती के दौरान जो बरामदगी हुई, वह दवाओं के रूप में थी, न कि

मादक या मनोदैहिक पदार्थों के रूप में।

(घ) वह स्थान जहां से वसूली की गई थी वह प्रत्यर्थी के कब्जे में नहीं था।

(ड.) कि अपराधों के वर्तमान लेनदेन का हिस्सा बनने के अलावा, आरोपी-प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई पूर्ववृत्त प्रतिबिंबित नहीं था।

17. इसके अलावा, दिनांक 27.09.2021 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, दिनांक 26.08.2021 के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर जमानत रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, यहां ऊपर बताए गए समान कारणों पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था।

18. इस प्रकार, यहां ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, जमानत रद्द करने के विषय पर कानून की स्थापित स्थिति, विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 द्वारा अधिरोपित युग्म अपेक्षाओं के पठित के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए अपराध के संबंध में, यह न्यायालय यह मानना उचित समझता है कि दिनांक 26.08.2021 का आक्षेपित आदेश अनुचित और विकृत तरीके से पारित किया गया था, और यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रकाश में उचित नहीं है, क्योंकि कोई *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि नहीं है विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी-प्रत्यर्थी के खिलाफ कथित अपराध या उसमें उसकी संलिप्तता के दोषी नहीं होने के आधार पर फैसला सुनाया जा सकता था। उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में, निम्नलिखित निष्कर्ष/टिप्पणियाँ उल्लेखनीय हैं:

18/1. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने, दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, तलाशी और जब्ती के दौरान बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को पर्याप्त व्यावसायिक मात्रा में होने के लिए कहीं भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। बल्कि, वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी का तथ्य एफआईआर के साथ-साथ निचली अदालत के समक्ष मामले के आकस्मिक रिकॉर्ड के अवलोकन से निर्विवाद रूप से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार, उपरोक्त गैर-विचारण आरोपी-प्रत्यर्थी की बेगुनाही के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई कथित संतुष्टि के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। इस संबंध में, 01.06.2021 को तैयार किए गए खोज और जब्ती मेमो का संदर्भ दिया गया है, जिसकी प्रासंगिक सामग्री यहां नीचे दी गई है:

टैब./कैप./इंज.	दवा का नाम	मात्रा (नग में)
टैब.	एनआरएक्स ट्रामाडोल	1,44,600
टैब.	एनआरएक्स ट्रामाडोल	2,40,000
टैब.	एनआरएक्स अल्प्राजोलम	59,400
टैब.	एनआरएक्स अल्प्राजोलम	84,000
कैप.	एनआरएक्स ट्रामाडोल	3,35,700
टैब.	एनआरएक्स ट्रामाडोल	39,600
इंज.	ट्रामाडोल एचसीएल	1.92 किग्रा
सिरप		60 किग्रा

18/2. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने, दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए, बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को दवाओं के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 238जैडएच और 178 के विश्लेषण में, विशेष रूप से साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची में उपरोक्त प्रतिबंधित पदार्थ शामिल हैं। इस प्रकार, दवाओं के समान होने का निष्कर्ष गलत और विकृत है, खासकर तब जब तस्करी की बरामदगी के समय, कोई वैध चालान प्रदर्शित नहीं किया गया था और इसे गुप्त रूप से स्वीकार किया गया था।

18/3. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए गलत राय दी है कि जिस स्थान से वसूली की गई थी वह आरोपी-प्रत्यर्थी के कब्जे में नहीं था। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि 'कब्जा' शब्द के अर्थ के विभिन्न रूप हैं और यह अपने अर्थ में काफी लोचदार है। कब्ज़ा और स्वामित्व हमेशा एक साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्यूनतम अपेक्षित तत्व जिसे पूरा करना होता है, वह है माल की हिरासत या नियंत्रण। इसलिए, यहां नीचे दिए गए तथ्यों पर संचयी विचार करने पर, यह पाया गया कि बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ आरोपी-प्रत्यर्थी के रचनात्मक कब्जे में था, क्योंकि *प्रथम दृष्टया* वह प्रतिबंधित पदार्थों/सामानों के नियंत्रण में था। आन्वयिक कब्जे को स्थापित करने वाले तथ्य हैं: (i) आरोपी-प्रत्यर्थी अर्थात वेलकम फार्मा के श्याम सुंदर मुंद्रा से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से बरामद 'किराया करार', जिस पर अभियुक्त-प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर हैं और उसे गवाह के रूप में दर्शाया गया है; (ii) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए 'प्रकटीकरण बयान', जिनमें शेख साजिद और कमल दीप मोर्या द्वारा दिए गए बयान भी शामिल हैं, जिसमें परिवहन के

लिए आरोपी-प्रत्यर्थी को प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध/गुप्त खरीद के रूप में विशिष्ट भूमिकाएं भी दी गई हैं और (iii) आरोपपत्र का संचयी वाचन, साथ ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान और साथ ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान जिसमें प्रथम दृष्टया उपरोक्त व्यक्तियों के बीच एक सांठगांठ स्थापित की गई है जिसमें पूरे अपराध को कारित करने में केंद्रीय भूमिका आरोपी-प्रत्यर्थी को दी गई है।

19. यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2021 का आक्षेपित आदेश समय से पहले पारित किया गया था, जबकि मामले में पर्याप्त जांच अभी भी लंबित थी। इस संबंध में, यह दर्शाया गया कि मामले में आरोप पत्र नवंबर, 2021 में दायर किया गया था, जबकि जमानत आदेश काफी पहले पारित किया गया था, जिससे विद्वान विशेष न्यायाधीश को प्रासंगिक और/या पर्याप्त जानकारी तक पहुंच के बिना आरोपी-प्रत्यर्थी की *प्रथम दृष्टया* भूमिका के बारे में खुद को संतुष्ट करने से रोका गया।

20. इसके अलावा, **तूफान सिंह (सुप्रा)** मामले में प्रत्यर्थी-अभियुक्त के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय जांच अधिकारी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों की अस्वीकार्यता को प्रमाणित करता है और इस अवलोकन को योग्य बनाता है कि आरोपी-प्रत्यर्थी को केवल सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर एक आरोपी बनाया गया था, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तथ्य के कारण अलग है कि उपरोक्त बयान राज्य द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को जमानत देने के खिलाफ उठाए गए एकमात्र आधार नहीं थे। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के आलोक में प्रत्यर्थी-अभियुक्त को जमानत न देने के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में राज्य द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई गईं। राज्य द्वारा दर्शाए गए अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए 'प्रकटीकरण वक्तव्य' बयानों से संबंधित हैं, जिनमें शेख साजिद और कमल दीप मोर्या द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान भी शामिल हैं, जिसमें अभियुक्त-प्रत्यर्थी को विशिष्ट भूमिकाएँ दी गई हैं, जैसे प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन के साथ-साथ अवैध/गुप्त खरीद और साथ ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत ईश्वर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 10.06.2021 को दिए गए बयान जिनमें प्रत्यर्थी-अभियुक्त की प्रत्यक्ष संलिप्तता को दर्शाया गया है।

21. यहां ऊपर दिए गए अंतर के समर्थन में, **एनसीबी बनाम मोहित अग्रवाल: (2022)**

एससीसी ऑनलाइन एससी 1891 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को यह निर्णय देने के लिए त्रुटिकर्ता नहीं ठहराया जा सकता है कि **तोफान सिंह (सुप्रा.)** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, अपीलकर्ता-एनसीबी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज प्रत्यर्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता था, जिसमें बहुमत के निर्णय के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए एक इकबालिया बयान को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का मुकदमे में अस्वीकार्य माना गया है। इसलिए, हिरासत में रहते हुए प्रत्यर्थी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति कि उसने अवैध रूप से मादक दवाओं का व्यापार किया था, को अलग रखना होगा। हालाँकि, यह एकमात्र सामग्री नहीं है जिस पर अपीलकर्ता-एनसीबी ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करने के लिए भरोसा किया था। अपीलकर्ता-एनसीबी ने विशेष रूप से कहा था कि यह प्रत्यर्थी द्वारा किया गया खुलासा था जिसके कारण एनसीबी टीम सह-अभियुक्त, प्रमोद जयपुरिया के गोदाम पर पहुंची और छापा मारा, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मनोवैज्ञानिक पदार्थों की टेबलेट, इंजेक्शन और सिरप के रूप में एक बडी खेप बरामद हुई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता-एनसीबी ने यह भी बताया था कि यह प्रत्यर्थी ही था जिसने सह-अभियुक्त प्रमोद जयपुरिया के पते और स्थान का खुलासा किया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्थी सहित सभी सह-अभियुक्तों के मोबाइल फोन के सीडीआर विवरण द्वारा यह खुलासा किया गया था कि वे एक-दूसरे के संपर्क में थे।*
>
> *17. "यहां तक कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए प्रत्यर्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान को भी खारिज कर दिया गया था, जिसे बाद में उनके द्वारा वापस ले लिया गया था, अपीलकर्ता-एनसीबी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से उच्च न्यायालय को हतोत्साहित होना चाहिए था। प्रत्यर्थी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह उचित ठहराने के लिए उचित आधार थे कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत इस तरह के अपराध का दोषी नहीं था। हम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा की गई दलील और आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणी से सहमत नहीं हैं कि चूंकि प्रत्यर्थी के कब्जे से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर ऐसी धारणा जल्दबाजी होगी।*

22. इस प्रकार, पूर्वोक्त पर भरोसा करते हुए, यह ध्यान रखना उचित होगा कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहने में

गलती की है जैसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए 'प्रकटीकरण वक्तव्य' और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान, जो *प्रथम दृष्टया* एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत आरोपी-प्रत्यर्थी के अपराध की संतुष्टि में सहायता कर सकते थे।

23. इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि आवेदक-राज्य की ओर से वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन दाखिल करने में देरी के बारे में आरोपी-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के आलोक में। उक्त हलफनामे के माध्यम से, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने अदालत को संतुष्ट किया कि वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदन दाखिल करने में देरी वर्तमान मामले के आईओ और वरिष्ठ कानून अधिकारी, होम जीआर. एक्स विभाग के बीच संचार के कारण उत्पन्न प्रक्रियात्मक देरी के कारण हुई थी, जिसमें आईओ को 27.09.2021 अर्थात विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत रद्दकरण आवेदन की अस्वीकृति की तारीख और 26.08.2022/27.08.2022 अर्थात वर्तमान आवेदन दाखिल करने की तारीख के बीच मौजूदा अवधि के दौरान प्रभारी अधिकारी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत भ्रष्टाचार की कुछ दुर्भावनाओं के कारण कई मौकों पर बदला गया था। इसलिए, उसी के आलोक में, वर्तमान जमानत रद्दीकरण आवेदन दाखिल करने में देरी के संबंध में उठाई गई आपत्ति तर्कसंगत नहीं है।

24. दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 के आक्षेपित आदेशों में विकृतियों के निष्कर्षों के अलावा, यह न्यायालय यह मानना भी आवश्यक समझता है कि वर्तमान मामले में कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिसके लिए आरोपी-प्रत्यर्थी को 26.08.2021 को दी गई जमानत को रद्द करना आवश्यक है।

25. इस संबंध में, यह देखा गया है कि 26.08.2021 को आरोपी-प्रत्यर्थी को जमानत देने के बाद, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत दिव्या मित्तल नामक एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही संचालित किए जाने के फलस्वरूप मामले का प्रभार रखने वाले दो जांच अधिकारियों को जांच शुरू होने के कारण विभाग द्वारा स्थानांतरित और/या निलंबित कर दिया गया था। यह देखा गया है कि उपरोक्त आईओ-दिव्या मित्तल को 21.01.2022 और 16.01.2023 के बीच की अवधि के दौरान मामले की जांच से निपटने के दौरान

एफआईआर संख्या 183/2021 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत इस आधार पर आरोपी बनाया गया था कि एक आरोपी-हिमालयन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून के मालिक सुनील नंदवानी को गिरफ्तार करने की मंजूरी दिए जाने के बावजूद आईओ-दिव्या मित्तल ने बिना कोई कानूनी कारण/आधार बताए उपरोक्त नामित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। इसके अलावा, एक अन्य जांच अधिकारी, श्री भूरा राम, जिनके पास 12.07.2021 और 20.01.2022 के बीच की अवधि के दौरान जांच का प्रभार था, को भी आरोपी-प्रत्यर्थी को जमानत दिए जाने के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था।

26. इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी-प्रत्यर्थी को दिनांक 26.08.2021 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के बाद और उसके बाद, मामले में उचित और निष्पक्ष जांच करने का कर्तव्य निभाने वाले दो जांच अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया और/या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत सह-अभियुक्तों की आवश्यकता के अनुसार गिरफ्तारी नहीं करने और गिरफ्तारी की मंजूरी दिए जाने के कारण आरोपी बनाया गया और वह भी इसके लिए कोई कारण बताए बिना, यह न्यायालय इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि आरोपी-प्रत्यर्थी द्वारा जांच में छेड़छाड़ की गई, जिससे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच के साथ-साथ मुकदमे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तदनुसार, उक्त अजीब परिस्थिति के आलोक में, आरोपी-प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय जिसमें आरोपी के साथ-साथ समन्वय द्वारा एफआईआर संख्या 197/2021, 195/2021 में कुछ सह-अभियुक्तों को जमानत दी गई है, इस न्यायालय की पीठ, अलग-अलग हैं और आरोपी-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क आवेदक-राज्य द्वारा रद्द किए जाने वाले आवेदनों को प्राथमिकता देने के लिए एक मनमाने ढंग से चुनने की व्यवस्था को अपनाने के लिए दिए गए हैं, भले ही सभी कथित अपराध एक से मामले से उत्पन्न हुए हों, सामान्य लेनदेन मान्य नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

27. इसलिए, इस तथ्य पर संचयी विचार करने पर कि दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 के आदेश प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिए बिना पारित किए गए थे, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना चाहिए था; कि आरोपी-प्रत्यर्थी को अप्रासंगिक विचारों के आधार पर जमानत दी गई थी, जिसका अवलोकन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के उचित अनुपालन

को इस संदर्भ में प्रतिबिंबित करने में विफल रहा कि विशेष न्यायाधीश ने आरोपी-प्रत्यर्थी की बेगुनाही के बारे में एक प्रथम दृष्टया संतुष्टि निर्मित कर ली; कि आरोपी-प्रत्यर्थी द्वारा मामले की उचित और निष्पक्ष जांच के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जांच में बार-बार होने वाले बदलाव के कारण आरोपी-प्रत्यर्थी को जमानत दिए जाने के बाद उत्पन्न हुई पर्यवेक्षी परिस्थितियों के आलोक में, जिनमें उन अधिकारियों, जिन्हें मामले में उचित जांच का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है, की बार-बार बदली की जा रही है, विशेष रूप से जांच अधिकारियों के आरोपी-प्रत्यर्थी के साथ प्रथम दृष्टया मिलीभगत की अतिरिक्त संभावना के बीच, जैसा कि तत्कालीन जांच अधिकारी सुश्री दिव्या मित्तल को जारी आरोप-पत्र के अवलोकन से पता चलता है; कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आधार पर, धारा 37 के तहत आरोपी-प्रत्यर्थी की कोई *प्रथम दृष्टया* निर्दोषता नहीं बनती है; कि **तोफान सिंह (सुप्रा.)** मामले में उच्चतम न्यायालय का आदेश वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं है, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप; कि तत्काल जमानत रद्दीकरण आवेदन दाखिल करने में हुई देरी कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण हुई थी, जिसे वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है और **वाई बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** और **मोहित अग्रवाल (सुप्रा.)** में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया जा सकता है, यह न्यायालय आवेदक-राज्य द्वारा दायर वर्तमान जमानत रद्दकरण आवेदनों को अनुमति देना उचित समझता है।

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी निचली अदालत के समक्ष लंबित मुकदमे के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

29. तदनुसार, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, तत्काल जमानत रद्द करने के आवेदनों की अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप, दिनांक 26.08.2021 और 27.09.2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द और आपास्त किया जाता है और आरोपी-प्रत्यर्थी को प्रदान की गई जमानत रद्द की जाती है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

Pooja/133-135

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।